

राजस्थान के जिला दुग्ध संघों में जल्द शुरू होगी भर्ती

जयपुर

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन(आरसीडीएफ), इससे संबद्ध इकाइयों और राज्यभर के जिला दुग्ध संघों में शीघ्र ही नई भर्तियां की जाएगी। राज्य सरकार से स्वीकृति मिलते ही नई भर्तियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने गुरुवार को आरसीडीएफ मुख्यालय में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि जिला दुग्ध संघों में रिक्त पदों की भर्ती की स्वीकृति अंतिम चरण में है, जल्द ही यह जारी दी जाएगी।

उन्होंने डेयरी फैडरेशन प्रबन्धन को पशु आहार क्रय समिति में दुग्ध संघों के तीन निर्वाचित अध्यक्षों को भी शामिल करने के निर्देश दिए जिससे खरीद प्रक्रिया को और अधिक बेहतर तथा पारदर्शी बनाया जा सके। बैठक में पशु आहार की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक में देवस्थान एवं गोपालन राज्यमंत्री ओटाराम देवासी और पशुपालन एवं गोपालन सचिव कुंजी लाल मीणा भी उपस्थित थे। सेस के लिए उच्चस्तरीय समिति समीक्षा बैठक में आरसीडीएफ द्वारा आर्थिक रूप से सुदृढ़ तथा कमजोर जिला दुग्ध संघों से समान रूप से सेस वसूलने के मुद्दे पर कृषि मंत्री सैनी ने एक उच्च स्तरीय समिति के गठन के निर्देश दिए। यह समिति राज्यभर के जिला दुग्धों संघों की वित्तीय स्थिति और सेस के वित्तीय प्रभाव का अध्ययन कर 15 दिन में उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि डेयरी फैडरेशन और जिला दुग्ध संघों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य दुग्ध उत्पादकों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान करना है न कि लाभ कमाना।

स्कूलों की जमीन पर खुलेगी दुग्ध समितियां समीक्षा बैठक में पशुपालन एवं गोपालन विभाग के शासन सचिव कुंजी लाल मीणा ने प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के दुग्ध भवन के

लिए जमीन आवंटन की मांग पर कहा कि हाल ही में 4500 प्राइमरी स्कूलों की जमीन खाली हुई है जिसे दुग्ध समितियों को आवंटन के लिए राज्य सरकार स्तर पर प्रयास किए जाएंगे।

समीक्षा बैठक के दौरान जयपुर डेयरी के अध्यक्ष ओम प्रकाश पुनिया, अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचन्द्र चौधरी, भीलवाड़ा डेयरी के अध्यक्ष रामलाल जाट सहित अन्य निर्वाचित अध्यक्षों ने अपने दुग्ध संघों की समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान आरसीडीएफ, डेयरी संघों के अधिकारी और जिला दुग्ध संघों के प्रबन्ध संचालक भी मौजूद थे।